



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 293] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 25 जुलाई, 2019

सं. टीएएमपी/11/2018-आईसीटीपीएल.—महापत्तन प्रशुल्क अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क अधिनियम एतद्वारा इसी क्रम में इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईसीटीपीएल) में अप-तटीय कंटेनर टर्मिनल में आरओआरओ/स्टील/कंटेनर संचालन के लिए मौजूदा तदर्थ दरों की वैधता में विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2018-आईसीटीपीएल

इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि.

—

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई 2019 के 24वें दिन पारित)

यह मामला इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईसीटीपीएल) में अपतटीय कंटेनर टर्मिनल पर आरओआरओ/स्टील कंटेनर संचालन के लिए मौजूदा तदर्थ दरों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 इस प्राधिकरण ने दिनांक 31 जुलाई 2018 के अपने आदेश के द्वारा मुंबई पोर्ट परिसर के भीतर विकसित अपतटीय कंटेनर टर्मिनल में आरओआरओ/स्टील कार्गो और कंटेनर संचालन के लिए चार्ज किए जाने वाले तदर्थ प्रशुल्क के निर्धारण के

लिए आईसीटीपीएल से प्राप्त प्रस्ताव का निस्तारण किया था। इस आदेश को भारत के राजपत्र में 11 सितंबर 2018 को राजपत्र नं.342 पर अधिसूचित किया गया था।

2.2. 31 जुलाई, 2018 के कथित आदेश के अनुसार, आईसीटीपीएल के संबंध में तदर्थ दरमान और सशर्तताएं 20 जुलाई 2015 से प्रभावी हो गयी हैं और परियोजना को पुनर्जीवित करने के समय या 31 मार्च 2019 तक या अन्यथा, इनमें से जो भी पहले हो, तक लागू रहना था। अनुमोदन, जब तक इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विस्तारित नहीं किया गया, स्वतः ही समाप्त हो जाना था।

3. इस पृष्ठभूमि में, आईसीटीपीएल ने अपने पत्र क्रमांक ओपीएस/टीओपी/ टीएएमपी/एल/1/19-20 दिनांक 3 मई 2019 में उल्लेख किया है कि परियोजना के पुनरोद्धार की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इस प्राधिकरण से दरमानों की मौजूदा वैधता 6 महीने की एक और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

4. हमने 7 मई, 2019 को इस मामले पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ आईसीटीपीएल के दिनांक 3 मई 2019 के पत्र की एक प्रति लाइसेंसधारी पोर्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) को भेज दी है। इसके जवाब में, एमबीपीटी ने अपने पत्र क्रमांक एफए/एसीसी/254-II/2300 दिनांक 13 जून 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:

- (i). एमबीपीटी को आईसीटीपीएल के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, यह सुझाव दिया गया है कि आईसीटीपीएल के लिए दरमानों को तदर्थ आधार पर तब तक माना जा सकता है जब तक कि उनके पुनः लागू करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या जब तक कि कोई नया प्रस्ताव जो भी पहले हो आईसीटीपीएल/एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता।
- (ii). इसके अलावा, एमबीपीटी के दरमानों में संशोधन का प्रस्ताव, टीएएमपी के विचाराधीन है और उसे को आईसीटीपीएल को अनुमति दिए जाने वाले कार्यों के संबंध में उपयोग किया जाएगा।
- (iii). टीएएमपी भी 01.04.2019 से आदेश को पूर्वव्यापी रूप से जारी कर सकता है।

5. आईसीटीपीएल द्वारा किए गए उल्लेखों के संबंध में, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईसीटीपीएल में अपतटीय कंटेनर टर्मिनल पर आरओआरओ/स्टील कंटेनर परिचालन के लिए मौजूदा तदर्थ दरों की वैधता 31 अप्रैल 2019 को पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस परियोजना को देखते हुए अभी तक इसे पुन लागू नहीं किया गया है और यह भी विचार किया जा रहा है कि एमबीपीटी ने मौजूदा एसओआर की वैधता के विस्तार के लिए अपनी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है और प्रशुल्क में एक रिक्तता से बचने के लिए, 31 मार्च 2019 के बाद आईसीटीपीएल मौजूदा एसओआर की वैधता का विस्तार करना उचित माना जाता है।।

6.1. प्रसंगवश, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईसीटीपीएल के दरमान का निर्धारण पूर्व में प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2005 के तहत शासित था, जिसे अब भारत सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2019 के तहत नियंत्रित किया जाएगा। प्रशुल्क गाइडलाइंस, 2019 की क्लॉज 1.6 में निहित शर्त के अनुसार, बीओटी ऑपरेटर्स जिनके प्रशुल्क गाइडलाइंस 2005 के तहत टीएएमपी द्वारा स्वीकृत दरमान(एसओआर) मान्य हैं, वे इस दौरान इन दिशानिर्देशों के तहत अपने एसओआर की समीक्षा के लिए एक प्रस्ताव दाखिल कर सकते हैं। मौजूदा एसओआर के लागू रहने या मौजूदा एसओआर की वैधता की समाप्ति के बाद। इस प्रकार, आईसीटीपीएल को प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार अपनी दरों में सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2005 के दिशानिर्देशों के तहत इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मौजूदा दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई है।

6.2. इस संबंध में, यह कहा गया है कि, जब लागत तथा दृष्टिकोण के बाद कंटेनर टर्मिनल के प्रशुल्क निर्धारण के लिए आईसीटीपीएल को प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया गया था, तब भी एमबीपीटी और आईसीटीपीएल ने एक ऐसी व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की जिससे एमबीपीटीएल आईसीटीपीएल को रिवाइवल प्रक्रिया पूरी होने तक कंटेनर सहित प्रशुल्क स्तर पर घाटभाड़ा के लिए एमबीपीटी के लिए अनुमोदित दरमानों में निर्धारित बर्थ भाड़े का 1.3 गुना अन्य कार्यों

आइटम्स के लिए आईसीटीपीएल को अनुमति देगा। इस व्यवस्था को इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आईसीटीपीएल को 31 जुलाई 2018 को प्रशुल्क ऑर्डर के तहत लागत की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद तदर्थ दरें लगाने की अनुमति दे दी गई है। चूंकि रिवाइवल प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए प्रशुल्क को तदर्थ आधार पर जारी रखना उचित माना जाता है।

7.1. आईसीटीपीएल ने 30 सितंबर 2019 तक 6 महीने की वैधता बढ़ाने की मांग की है। एमबीपीटी ने हालांकि, सुझाव दिया है कि आईसीटीपीएल के लिए दरों के तदर्थ दरमानों की वैधता को तब तक माना जा सकता है जब तक कि पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या एक नई अवधि तक के लिए प्रस्ताव आईसीटीपीएल/एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो भी पहले हो। हालांकि, एमबीपीटी ने परियोजना के पुनरुद्धार के लिए समय सीमा का संकेत नहीं दिया है।

7.2. आईसीटीपीएल के संबंध में पुनरोद्धार प्रक्रिया पूरी करने के लिए एमबीपीटी द्वारा इंगित एक विशिष्ट समय सीमा के अभाव में, एमबीपीटी की अनिश्चित अवधि के आधार पर, अनिश्चित काल के लिए आईसीटीपीएल की तदर्थ दरों की वैधता का विस्तार करना उचित नहीं समझा गया है। उसी समय, आदेश पारित होने पर अधिसूचना में लगने वाले समय पर विचार करते हुए यदि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो एमबीपीटी/आईसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर विचार करते हुए, आईसीटीपीएल के अनुरोध के अनुसार, 30 सितंबर 2019 तक वैधता का विस्तार भी एक छोटी अवधि मानी जाती है।

7.3. इस प्रकार, पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिए गए कारणों के आधार पर और समग्र सोच-विचार के आधार पर, यह प्राधिकरण, प्रशुल्क में उत्पन्न शून्यता से बचने के लिए और एमबीपीटी के अनुरोध पर, आईसीटीपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता में 01 अप्रैल 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 मार्च 2020 तक या जब तक कि आईसीटीपीएल के संबंध में पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, या अन्यथा, जो भी पहले हो पूर्वव्यापी प्रभाव से विस्तार करता है।

7.4. इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान, जब तक पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी होती है, आईसीटीपीएल को, वर्तमान में आईसीटीपीएल के संबंध में लागू प्रशुल्क के संबंध में प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के आधार पर अपना प्रस्ताव दायर करना चाहिए।

8. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमबीपीटी के मौजूदा दरमानों में संशोधन किए जाने हैं। क्योंकि, आईसीटीपीएल को, एमबीपीटी पर लागू होने वाली घाट दरों को लागू करने और एमबीपीटी के बर्थ किराया शुल्क के 1.3 गुना पर बर्थ किराया शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, अतः, एमबीपीटी में तदसमयानुरूप लागू एमबीपीटी के संशोधित दरमान, जैसा कि एमबीपीटी ने सहमति व्यक्त कर दी है, आईसीटीपीएल के लिए लागू होंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./180/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 25th July, 2019

No. TAMP/11/2018-ICTPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing adhoc scale of rates for RORO / Steel / Container Operations at Offshore Container terminal at Indira Container Terminal Private Limited (ICTPL), as in the order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/11/2018-ICTPL

Indira Container Terminal Private Limited

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 24th day of July 2019)

This case deals with the extension of the validity of the existing adhoc scale of rates for RORO / Steel / Container Operations at Offshore Container terminal at Indira Container Terminal Private Limited (ICTPL).

2.1 This Authority vide its Order dated 31 July 2018 had disposed of the proposal received from ICTPL for fixation of adhoc tariff to be charged for RORO / Steel / Cargo and Container Operations at Offshore Container Terminal developed within the Mumbai Port Premises. This Order was notified in the Gazette of India on 11 September 2018 vide Gazette No.342.

2.2. As per the said Order dated 31 July 2018, the adhoc Scale of Rates and conditionalities in respect of ICTPL have come into effect from 20 July 2015 and was to be in force till the time the project is revived or upto 31 March 2019, or otherwise, whichever is earlier. The approval accorded was to automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

3. In this backdrop, the ICTPL vide its letter No. OPS/TOP/TAMP/L/ 1/19-20 dated 3 May 2019 has stated that project revival process is not yet completed and has requested this Authority to extend the validity of the existing scale of rates for another period of 6 months.

4. We have vide our letter dated 7 May 2019 forwarded a copy of the ICTPL's communication dated 3 May 2019 to the Licensor Port Mumbai Port Trust (MBPT) with a request to furnish its comments on this matter. In response, the MBPT vide its letter No. FA/ACC/254-II/2300 dated 13 June 2019 has made the following submissions:

- (i). The MBPT does not have any objection to the proposal of ICTPL. However, it is suggested that the adhoc scale of rates for ICTPL can be considered till the process of revival is completed or till a new proposal is submitted by ICTPL / MBPT, whichever is earlier.
- (ii). Further, the revision proposal of MBPT scale of rates is under consideration of the TAMP and the same shall be used by ICTPL in respect of cargo allowed to them.
- (iii). TAMP may also like to issue the order retrospectively from 01.04.2019.

5. With regard to the submissions made by ICTPL, it is relevant here to mention that the validity of the existing adhoc scale of rates for RORO / Steel / Container Operations at Offshore Container terminal at ICTPL has already expired on 31 March 2019. Considering that the project is yet to be revived and also considering that the MBPT has conveyed its no objection for extension of validity of the existing SOR and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR of ICTPL beyond 31 March 2019.

6.1. Incidentally, it is relevant here to state that the fixation of SOR of ICTPL was previously governed under the Tariff Guidelines, 2005 which will be now governed under the Tariff Guidelines, 2019 issued by the Government of India. As per the stipulations contained at clause 1.6 of the Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators whose Scale of Rates (SOR) approved by TAMP under the Tariff Guidelines 2005 are valid may either file a proposal for review of their SOR under this Guidelines during the currency of the existing SOR or after expiry of the validity of the existing SOR. As such, the ICTPL is required to file proposal for general revision of its scale of rates as per the Tariff Guidelines, 2019, as the validity of the existing SOR approved by this Authority under 2005 guidelines has expired on 31 March 2019.

6.2. In this connection, it is stated that, even when the ICTPL was governed by the Tariff Guidelines of 2005 for fixation of tariff for the container terminal following cost plus approach, the MBPT and the ICTPL have agreed for an arrangement whereby MBPT will permit ICTPL to handle other cargo items including container at the tariff level approved for MBPT for wharfage and 1.3 times of the berth hire prescribed in the SOR of MBPT till the revival process is completed. This arrangement has been accepted by this Authority and the ICTPL has been permitted to levy the rates on adhoc basis after analysing the cost position vide tariff order dated 31 July 2018. Since the revival process is not yet completed, it is felt appropriate to continue adhoc tariff arrangement.

7.1. The ICTPL has sought extension of validity for a period of 6 months upto 30 September 2019. The MBPT has, however, suggested that the validity of the adhoc scale of rates for ICTPL can be considered till the process of revival is completed or till a new proposal is submitted by ICTPL / MBPT, whichever is earlier. The MBPT has, however, not indicated the time frame for revival of project.

7.2. In the absence of a specific time frame indicated by MBPT for the completion of the revival process in respect of ICTPL, it is not felt appropriate to extend the validity of adhoc rates of ICTPL on an indefinite basis, as suggested by MBPT. At the same time, considering the time involved in notification of the Order (to be) passed on the proposal if submitted by MBPT / ICTPL, the extension of validity till 30 September 2019, as requested by ICTPL, is also felt to be a short period.

7.3. Thus, based on the reasons as brought out in the preceding paragraphs and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of existing SOR of ICTPL retrospectively from 01 April 2019 (so as to avoid vacuum in tariff and as requested by MBPT) for a period of one year i.e. upto 31 March 2020 or till the revival process is completed in respect of ICTPL, or otherwise whichever is earlier.

7.4. In the intervening period, as and when the revival process is completed, the ICTPL should file its proposal for fixation of its tariff based on the Tariff Guidelines, 2019, which is now applicable in respect of ICTPL.

8. It is relevant to mention here that the existing rates of MBPT is due for revision. Since the ICTPL has been authorised to levy wharfage rates as applicable to MBPT and to levy berth hire charges at 1.3 times of the MBPT berth hire charges, the revision in the SOR of MBPT, as and when applicable to MBPT, shall also apply to the ICTPL, as agreed by MBPT.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./180/19]